weightage to Gadchiroli for development of industries.

SHRI MURASOLI MARAN: I understand the anger of the hon. Member because backwardness is the biggest problem staring at our face. Probably because he could not show his anger to the Planning Minister, he is showing it to me. Anyhow I understood the matter and I will definitely devote more time to this problem.

*403. *[The Questioner (Shri Amar Singh) was absent for answer vide col. 29 infra.]*

Export of coal

*404. SHRI SHIV CHARAN SINGH:†
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the details of coal excavated from different coal mines during each of the preceding three years;

(b) whether any part of this had been exported;

(c) if so, details of the quantity thereof and foreign exchange earned thereby; and

(d) the countries to which the coal was exported?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shiv Charan Singh.

Statement

(a) The details of coal production from the mines of Coal India Ltd. (CIL) Singareni Collieries Co. Ltd. (SCCL) and captive collieries during the last three years are as under:-

(million tonnes)

	1994-95	1995-96	1996-97 (Provisional)
CIL	223.07	237.28	250.65
SCCL	25.65	26.77	28.73
CAPTIVE COLLIERIES (TISCO, IISCO & DVC)	5.01	6.08	6.28
TOTAL	253.73	270.13	285.66

(b) Yes, Sir.

(c) The quantity of coal exported by Coal India Limited and foreign exchange earned during the last three years are as under:

(Figs. in 000 tonnes)

Year	Quantity exported	Foreign exchange earned
1994-95	111.9	US$ 2.14 Million
1995-96	92.0	US$ 1.44 Million
1996-97	126.8	US$ 1.74 Million

Export to Nepal and Bhutan is made in Indian Rupees.

(d) Coal is exported only to Bangladesh, Nepal and Bhutan.

श्री शिवचरण सिंह: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदया जी ने जो उत्तर दिया है उसमें मैंने पूछा तो यह था कि खान वार उत्पादन क्या है? लेकिन उन्होंने खानों का, सबको इकट्ठा करके कम्पनी वार दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मंत्री महोदया मुझे यह बताने की कृपा करें कि इन कम्पनियों में ओपन कॉस्ट से कितना कोयला निकलता है और अंडर ग्राउंड से कितना निकलता है तथा उसकी क्वालिटी और ग्रेड क्या है?

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति महोदय, इसके तो अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन मैं डिटेल इनको भिजवा दूंगी कि ओपन कॉस्ट से कितना हमारा प्रोडक्शन है और अंडर ग्राउंड माइन्स से कितना प्रोडक्शन है।

श्री शिवचरण सिंह: सभापति महोदय, मैंने खान-वार आंकड़े मांगे थे, आपने खानवार नहीं दिये, कम्पनी-वार दे दिये। जब कम्पनी वार दे दिये तो मैंने पूछा कि ओपन कॉस्ट कितना है और अंडर ग्राउंड कितना है, वह आंकड़े भी आपके पास नहीं है। मैंने पूछा कि क्वालिटी क्या है तो वह भी आपके पास नहीं है। फिर क्या उत्तर आप दे रही हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह: जो डिटेल आपने मांगा है कि कितना प्रोडक्शन ओपन कॉस्ट से है।

श्री शिवचरण सिंह: ओपन कॉस्ट और अंडर ग्राउंड दोनों तरीके से अलग-अलग प्रोडक्शन होता है, उसका आप बताएं तो मैं दूसरा प्रश्न करूं।

श्रीमती कान्ति सिंह: इसकी पूरी डिटेल मैं आपको भेज दूंगी। आपने आयात और निर्यात पर प्रश्न किया था।

श्री शिवचरण सिंह: आयात और निर्यात का तो मुझे मालूम है कि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम ऐक्सपोर्ट करते हैं 0.09 मिलियन टन और इम्पोर्ट करते हैं 13.23 मिलियन टन। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदया आपको ज्ञात होना चाहिए कि सारे मेघालय प्रान्त से - मेघालय में जितनी कोयला खानें हैं, वही भारत सरकार के अंतर्गत नहीं है। वह पंचायतों के हाथ में है और उस सारे कोयले को वहां के किसान चेरापूंजी और आस-पास के इलाकों में से निकालते हैं। अब वह सारा कोयला चोरी से बांग्लादेश जाता है। वह आपने इसमें शामिल नहीं किया है। आपने भूटान और नेपाल के निर्यात के आंकड़े दिये हैं और कहा है कि नेपाल और भूटान को निर्यात भारतीय रुपये में किया जाता है। तो जो आपने 2.14 मिलियन टन बताया है जिसका ऐक्सपोर्ट आपने 111.9 दिखाया है, यह कौन से देश से मिलता है?

श्रीमती कान्ति सिंह: यह बांग्लादेश से मिलता है।

श्री शिवचरण सिंह: तो क्या इसमें वह रकम भी शामिल है जो मेघालय से चोरी से माल जाता है? (व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह। उसको हम कैसे आपको देंगे? (व्यवधान)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वह कैसे उसमें देंगे? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इट इज़ मिनिस्टर्स प्रापर्टी। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: क्या भारत सरकार की प्रापर्टी नहीं है? (व्यवधान) मेघालय और गोवाहाटी से जो रहा है (व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह: अगर इस तरह की बात है कि चोरी से यह ज्यादा जाता है तो जो आप बता रहे हैं इसका कोई (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: क्या उसको रोकने के लिए आप कोई प्रयत्न करेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: आप मंत्री महोदया को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: वहां चोरी होती है। मैंने आंखों से देखा है। मैं वहां गया था। वहां कमेटी जाती है (व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Border Security Force and the Customs officials would know that. How can she know that?

MR. CHAIRMAN: There are no figures about the smuggling. How can the Minister give them?

श्री शिवचरण सिंह: क्या भारत सरकार इस चोरी को रोकने का कोई प्रयत्न करेगी?

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, हमारे देश में कोयले का विशाल भंडार है और अच्छी क्वालिटी का है। एक ओर तो हम अपने देश में जो कोयले की मांग है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर हम कोयले का निर्यात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम अपने देश की कोयले की मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और इसको हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो इसको देश से निर्यात करने के क्या कारण हैं, क्या लाजिक है, क्या औचित्य है? मेरे प्रश्न का यह पहला भाग है और भाग "ख" मेरा यह है कि इन्होंने निर्यात की, एक्सपोर्ट की फिगर्स दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अवधि में आपने कितने रुपयों का आयात किया है और किस दर पर आप कोयला आयात करते हैं और किस दर पर आप बाहर एक्सपोर्ट करते है?

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति महोदय, हमारे देश में लो एश कोकिंग कोल का इम्पोर्ट होता है। स्टील प्लांट्स द्वारा ऐसे कोयले की मांग है इसलिए स्थानीय उपलब्धता का जो गैप है इससे उसको दूर किया जाता है। हम उसको ब्लेडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। नान-कोकिंग कोल

मुख्यत: समुद्र तट पर स्थित विद्युत तापघरों और सीमेंट प्लांटों में इस्तेमाल होता है जहां पर परिवहन या अन्य कमर्शियल कारणों से यह सुविधाजनक होता है। जहां तक एक्सपोर्ट का प्रश्न है यह हमारे वार्षिक उत्पादन का 0.5 प्रतिशत से भी कम है। अत: इससे देश की कोयले की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

जहां तक इम्पोर्ट की बात आपने कही तो हमारे यहां 1995-96 में जो कोकिंग कोल है वह 9.37 मिलियन टन और नान-कोकिंग कोल और अन्य कोक 4.31 मिलियन टन, टोटल 13.62 मिलियन टन है और इसकी कीमत 3093 करोड़ रुपाए है जो हमें इम्पोर्ट से मिलता है।

श्री गोविन्दराम मिरी: मैंने रेट पूछा है, रेट आफइम्पोर्ट?

श्रीमती कान्ति सिंह: मैं टोटल आप को बता रही हूं।

महोदय, 1996-97 में, जो एक्सपोर्ट हुआ उसकी फिगर्स मेरे पास है जो इंडिया में घरेलू उपयोग में लिया जाता है वह है, 1499.37 और जब हम नेपाल में....

श्री नरेन्द्र मोहन: सर, दि क्वेश्चन इज अबाउट दि रेट।

श्रीमती कान्ति सिंह: रेट ही मैं बता रही हूं। जो हमारे घरेलू उपयोग में कोल लाया जाता है, 1996-97 में 1499.37 पर टन और जब हम नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका 1975.10 है और जब हम बंगला देश में उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वह 1831 है।

श्री गोविन्दराम मिरी: इसे जो हम आयात करते हैं इससे हमें फायदा होता है या नुकसान होता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह: जब हम निर्यात करते हैं तो इसमे हमें फायदा होता है।

श्री गोविन्दराम मिरी: और हम कम रेट में आयात करते हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह: कोयले की अलग अलग क्वालिटी हैं जो इम्पोर्ट की जाती है। कोकिंग कोल जो इम्पोर्ट होता है स्टील प्लांट्स में उसको यूज में लाया जाता है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि नेपाल और बंगला देश को जो कोयला बेचा जाता है उसमें हम मुनाफा कमाते हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश द्वारा कोयला बेचा जाता है उसके लिए रायल्टी फिक्स है जो बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और कोयला खदानों के राज्यों को दी जाती है। जो कोयला एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें आप जो मुनाफा कमाते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के कोयले से जो आप अर्न करते हैं तो जो एक्सपोर्ट बेनिफिट - कोई भी कंपनी जब किसी चीज का एक्सपोर्ट करती है तो उस कंपनी को उसका बेनिफिट मिलता है, तो जब हम माइनिंग रायल्टी लेते हैं तो उस एक्सपोर्टेड क्वांटिटी की रायल्टी क्या आपने कोई अलग से फिक्स की है? अगर की है तो क्या की है और अगर नहीं की है तो क्या आप इसे करने जा रहे हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह: यह तो अलग से प्रश्न किया गया है लेकिन कोयले पर जो रायल्टी पहले से फिक्स है, जो एक्सपोर्ट होता है, उस पर भी सेम रायल्टी होती है।

श्री मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कोयला मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। कोयले के एक्सपोर्ट के बारे में इन्होंने बंगलादेश को एक्सपोर्ट का ज़िक्र किया। मेघालय से कोयला बंगलादेश भेजते वक्त पिछले कई वर्षों में जो घोटाला हुआ, कोल स्कैम हुआ, जितने रुपये का कोयला वहां भेजा गया और बैंक के माध्यम से शिलांग में पेमेंट हुआ, इसके बारे में जानकारी क्या आपके मंत्रालय के पास है, अगर है तो आपने क्या कदम उठाए और अगर नहीं है तो क्या आप वित्त मंत्रालय से, बैंकिंग डिपार्टमेंट से और बैंक आफ बड़ौदा की शिलांग ब्रांच से इस बारे में जानकारी लेंगे और कोई कदम उठायेंगे या नहीं?

†جناب محمد سلیم: سبھاپتی مہودے - آپکے مادھیم سے میں کوئلہ منتری جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں - کوئلے کے ایکسپورٹ کے بارے میں انھوں نے بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کا ذکر کیا - میگھالیہ سے کوئلہ بنگلہ دیش بھیجتے وقت پچھلے کئی ورشوں میں جو گھوٹالہ ہوا "کول اسکیم" ہوا - جتنے روپیہ کا کوئلہ وہاں بھیجا گیا اور بینک کے مادھیم سے شیلانگ میں پیمنٹ ہوا - اسکے بارے میں جانکاری کیا آپکے منترالیہ کے پاس ہے اگر ہے تو آپنے کیا قدم اٹھائے اور اگر نہیں ہے تو کیا آپ "وت منترالیہ" سے "بنکنگ ڈیپارٹمنٹ" سے اور بنک آف بڑودہ کی شیلانگ برانچ سے اس بارے میں جانکاری لینگے اور کوئی قدم اٹھائینگے یا نہیں؟

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति महोदय, इसमें जानकारी अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि यह अलग से प्रश्न किया गया है। इसकी जानकारी मैं प्राप्त कर लूंगी और आपको भिजवा दूंगी।

श्री नरेन्द्र मोहन: मंत्री जी, कृपा कर के यह बताएं कि यह जो मेघालय और आसाम के क्षेत्रों से बंगलादेश को कोयला स्मगलिंग हो कर के जा रहा है, क्या यह बात आपकी जानकारी में आ गई है? इसको रोकने के लिए क्या आप कोई नीति बनाएंगे और सदन को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे? यह एक पेचीदा सवाल उठता है। दूसरा सवाल यह है कि काफी अरसे से यह बात चली आ रही है। क्या वजह थी कि यह सूचना आपके पास नहीं पहुंची जबकि इसकी पूरी जानकारी वित्त मंत्रालय को भी, राज्य सरकार को भी हो रही थी, आपके पास क्यों नहीं पहुंची? क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने कोई यंत्र बनाया है, संगठन बनया है, कोई व्यवस्था की है या नहीं की है?

श्रीमती कान्ति सिंह: जैसे कि अभी मेघालय से कोयले की चोरी के संबंध में आपने कहा। मेघालय से हैंडपिक्ड कोयला भी निर्यात किया जाता है और यह मेघालय स्टेट से रिलेटड है ...(**व्यवधान**)

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं केवल चोरी की बात पूछ रहा हूं। निर्यात की बात, जो आफिशियली एक्सपोर्ट होता है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए चूंकि अब आपकी जानकारी में बात आई है क्या आप कोई स्पष्ट नीति बनाएंगे और सदन को आश्वास्त करेंगे कि भविष्य में स्मगलिंग नहीं होगी। क्या आप यह आवासन देने को तैयार हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह: जो इसकी डिटेल्ड बातें हैं, इसकी सारी डिटेल मैं आपके पास भिजवा दूंगी (**व्यवधान**) क्योंकि यहां पर वर्तमान में सभी प्रकार के कोयले के संबंध में जिसमें मेघालय का कोयला भी शामिल है बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जाता है। पहले से रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई है। क्योंकि मेघालय में कमर्शियल एक्सप्लायटेशन पोसिबल नहीं है इसलिए हम लोग इस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हम इस पर पहल करेंगे ...(**व्यवधान**)

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, my question has not been answered at all.

श्रीमती कान्ति सिंह: जो चोरी की बातें हैं, हम उसे रोकने के लिए प्रयास करेंगे।

*405. [*The Questioner (Shri Gyan Ranjan) was absent. For answer vide Col. 30 infra*]

Wastage of cement in jute bags

*406. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is a high degree of wastage of cement packed in jute bags due to seepage in handling and atmospheric effect;

(b) whether any studies have been conducted as to quantum of such wastage if cement was packed in jute and synthetic bags respectively and the findings of the studies;

(c) whether Government have received representations from the synthetic bag manufacturers as well as the cement industry to withdraw the order that requires fifty per cent packing of cement in jute bags so as to save wastage and cater to consumers preference for synthetic bags; and

(d) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b): According to a techno-market study conducted by the Technology Information Forecasting & Assessment Council (TIFAC), Department of Science & Technology in January, 1992, seepage loss of cement when packed in jute bags has been estimated at 4% as against 1% when packed in synthetic bags.

(c) and (d): A number of representations have been received from synthetic bag manufacturers and the cement industry for withdrawal of the Jute bags Reservation Order in the case of cement industry. The representatives of these industries have also placed their views before the Standing Advisory Committee constituted under the Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987. The Government will take a final decision after considering the recommendations of the said Committee.